

भूगोल की दो शाखाओं—भौतिक और मानव भूगोल की अनेक उप-शाखाएँ हैं जो उनके विशेष अध्ययन के नाम से सम्बोधित की जाती हैं । आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विविधताओं, विशेषताओं, स्थानिक प्रतिरूपों तथा पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है । आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव प्रयत्नों (आर्थिक क्रिया-कलापों) पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का आकलन और विश्लेषण करना है ।

आर्थिक भूगोल के अन्तर्गत मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक क्रिया-कलाप (आखेट,

मत्स्य पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना, कृषि, खनन, उद्योग-धन्धे, परिवहन व्यापार इत्यादि करता है। इन आर्थिक क्रिया-कलापों पर भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, परिवहन के साधन इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। इन आर्थिक क्रिया-कलापों का विश्लेषणात्मक एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है।

## 1.2 परिभाषा (Definition)

1882 ई० में जर्मनी के गाट्ज (Gotz) ने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल को निम्न रूप में परिभाषित किया : "आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।"

"Economic Geography makes a scientific investigation of nature of World areas in their direct influence on the production of goods."

ई० डब्लू जिम्मेमैन (E. W. Zimmerman) के अनुसार "आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक जीवन की व्याख्या उसके वातावरण के संदर्भ में करता है।"

"Economic Geography deals with the economic life of man with relation to environment."

सी० एफ० जोन्स एवं डार्कनवाल्ड (C. F. Jones and Darkenwald) ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि "आर्थिक भूगोल के अन्तर्गत मानव के उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन किया जाता है साथ ही साथ यह संकेत करता है कि क्यों कोई प्रदेश किसी वस्तु के उत्पादन एवं निर्यात में अग्रणी है तथा क्यों अन्य प्रदेश इन वस्तुओं के आयात एवं उपभोग में महत्वपूर्ण है।"

"Economic Geography deals with the productive occupation and attempts to explain why certain regions are outstanding in the production and export of various articles and why others are significant in the import and utilization of these products."

जी० जी० चिशोल्म (G. G. Chisholm) के अनुसार "आर्थिक भूगोल के अन्तर्गत उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा विनिमय को प्रभावित करती है। आर्थिक भूगोल का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा हमें भविष्य में किसी प्रदेश के वाणिज्यिक विकास की स्थिति का ज्ञान हो जाता है और यह पता चलता है कि उस पर भौगोलिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है।"

"It (Economic Geography) embraces all geographical conditions affecting the production, transport and exchange of commodities. Its chief use is to enable us to form some reasonable estimate of the future course of commercial development so far as that is governed by geographical conditions."

आर० ई० मर्फी (R. E. Murphy) के अनुसार "आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं एवं विषमताओं का अध्ययन करता है।"

"Economic Geography has to do with similarities and differences from place to place in the ways people make a living".

रिचर्ड हार्टशोर्न (Richard Hartshorne) एवं जे० डब्लू एलेक्जेंडर (J. W. Alexander) ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि—"आर्थिक भूगोल पृथ्वीतल की क्रियाओं की स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है जो उत्पादन, विनिमय तथा वस्तुओं के उपभोग तथा सेवाओं से संबंधित है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य इन स्थानिक विभिन्नताओं के व्याख्या करने के क्रम में सामान्यीकरण एवं सिद्धान्तों को विकसित या प्रतिपादित करना है।"

"Economic Geography is the study of the spatial variation on the earth's surface of activities related to producing, exchanging and consuming goods and services. Whenever possible the goal is to develop generalization and theories to account for these spatial variations."

उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

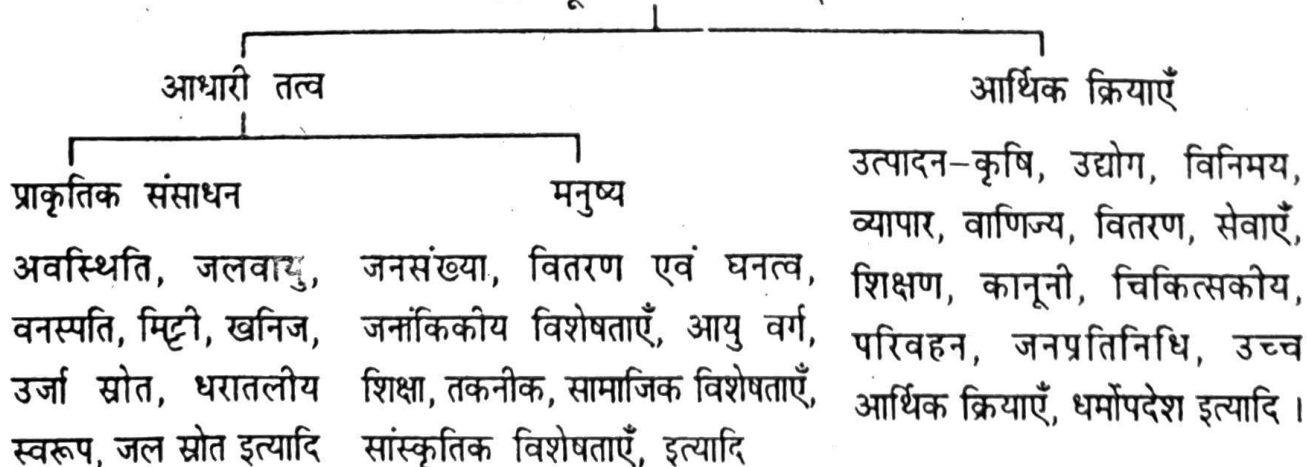
1. आर्थिक भूगोल जीविकोपार्जन के ढंगों और उनकी समस्याओं से संबंधित विज्ञान है जिसमें भूतल के आधारभूत संसाधनों और उनसे संबंधित मानव क्रियाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक भूगोल मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग (विदोहन) से संबंधित विज्ञान है, जिसमें उसके उत्पादन, परिवहन वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है।
2. आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय विविधताओं को भौतिक एवं मानवीय संदर्भों में देखने का प्रयास करता है। जब प्राकृतिक एवं मानवीय परिवेश के कारकों में आर्थिक उद्देश्यों से अन्तर्प्रक्रिया आरम्भ होती है तो क्षेत्रीय वैविध्य उभरता है। आर्थिक भूगोल इसी क्षेत्रीय विकास का अध्ययन करता है।
3. क्षेत्रीय विभिन्नताओं की व्याख्या करने के क्रम में सामान्यीकरण एवं सिद्धान्तों का विकास संभव हो पाता है।

### 1.3 विषय क्षेत्र (Scope)

आर्थिक भूगोल का अध्ययन विषय, जीवन स्तर के प्रादेशिक प्रतिरूपों का निरूपण करने के साथ ही उन प्रतिक्रियाओं का विवेचन करना है जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में प्रादेशिक विषमताएँ प्रकट होती हैं। आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य है—मानव कल्याण की दृष्टि से उन बाधाओं को दूर करना जिनसे विभिन्न प्रदेशों के मनुष्यों का जीवन-स्तर गुणात्मक दृष्टि से एक समान स्थिति (सड़क स्थिति) में नहीं रह पाता तथा उन प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना जिनसे गुणात्मक जीवन-स्तर में प्रादेशिक विसंगति दूर हो सकें।

आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसका संबंध मनुष्य के भोजन, वस्त्र, आवास और आराम की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए मनुष्य द्वारा किये गये आर्थिक प्रयत्नों से है। दूसरे शब्दों में— आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मानव पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का उपयोग करता है, विभिन्न वस्तुओं का (कच्चा माल, खाद्यान्न, तैयार माल इत्यादि) उत्पादन करता है और किस प्रकार उनका परिवहन, वितरण उपभोग या विनिमय करता है। वस्तुतः आर्थिक भूगोल में हम प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ (Where), क्यों (Why), कैसे (How), और कब (When) उपयोग किया जाता है, आदि प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इसके अन्तर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के आधारी तत्व एवं आर्थिक क्रियाएँ आती हैं।

#### आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र





उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधन एवं मनुष्य आर्थिक भूगोल के आधारी या मूलभूत तत्व है जिनके आपसी अंतर्क्रिया (Interaction) के कारण विभिन्न आर्थिक क्रियाएँ विकसित होती है। साथ ही साथ इसके विषय क्षेत्र की परिधि में सम्पूर्ण मानव वातावरण तंत्र सम्मिलित है, जैसे—

1. विभिन्न तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप।
2. तकनीकी विकास क्रम के संदर्भ में इस कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया।
3. अन्तर्प्रादेशिक एवं प्रादेशिक अन्तःप्रक्रिया
4. उपरोक्त तीनों का पर्यावरण (विशेषतः परिस्थितिकी संतुलन तथा दीर्घकालीन परिपेक्ष्य में गुणात्मक जीवन-स्तर पर प्रभाव का अध्ययन,

आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के संदर्भ में उपरोक्त चार विचारधाराएँ प्रचलित हैं, जिनका विशद वर्णन निम्नांकित है—

1. विभिन्न तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप : इस विचारधारा के अनुसार ऐसे सभी आर्थिक क्रिया-कलाप जो भूतल पर अपना चिह्न छोड़ते हैं अर्थात् कहीं-न-कहीं मूर्त रूप में प्रकट होते हैं, आर्थिक भूगोल के मूलाधार हैं, जैसे—कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन इत्यादि। अन्य शब्दों में—सभी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक कार्य जिनका भूतल पर ठोस रूप दृष्टि होता है, आर्थिक भूगोल की अध्ययन परिधि में शामिल है।

अब प्रश्न यह उठता है कि उक्त वर्गों के अनेकानेक कार्य, जैसे—कृषि, खनन, उद्योग, वाणिज्य परिवहन इत्यादि में से प्रत्येक का गहन अध्ययन अन्य कई संबंधित विषयों, जैसे—कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, खनन विज्ञान द्वारा किया जाता है। फिर आर्थिक भूगोल द्वारा इन सबका सम्मिलित अध्ययन करने का औचित्य या सार्थकता क्या है? इसका एक साधारण उत्तर यह है कि संबंधित विषय किसी एक आर्थिक कार्य जैसे कृषि के संगठनात्मक एवं व्यवस्थापक पक्ष का अथवा प्रत्येक वर्ग के किसी एक तत्व जैसे गेहूँ अथवा लौह-अयस्क के उद्भव-विकासात्मक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, जबकि आर्थिक भूगोल प्रत्येक कार्य-वर्ग अथवा तत्व के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर ध्यान केन्द्रित करता है। साथ ही साथ आर्थिक भूगोल किसी क्षेत्र विशेष में विविध आर्थिक तत्वों एवं कार्यों के परस्पर अंतर्संबंध एवं उससे उत्पन्न समुच्चयिक स्वरूप पर विशेष ध्यान केन्द्रित करता है। दूसरे शब्दों में आर्थिक भूगोल किसी प्रदेश के भूवैन्यासिक संगठन में प्रत्येक आर्थिक तत्व अथवा कार्य की कार्यात्मक भूमिका (Functionability) तथा अन्य तत्वों/कार्यों से कार्यात्मक अन्योन्याश्रितता (Functional interdependency) के अध्ययन पर बल देता है। रिचर्ड मैरिल के अनुसार, भूवैन्यासिक संगठन का तात्पर्य मानव समाज द्वारा क्षेत्र में समाकलित/कुल उपयोग (Aggregate use of space by society) है। अन्य शब्दों में अर्थतंत्र का क्षेत्रीय संगठन मानव कार्य-कलाप के परस्पर 'अंतर्संबंधित पूंज (Clusters of Human Activities Interrelated with Each Other) का द्योतक है जिसके निम्नलिखित तीन प्रमुख संघटक हैं :—

- (i) ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास, जो कृषि, खनिज, व्यापार, उद्योग एवं विभिन्न सेवाओं के केन्द्र होते हैं। ये अधिवास मानव के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अंतर्प्रक्रिया (Interaction) के प्रतिफल होते हैं,
- (ii) अधिवासों को अन्तर्संबंधित करनेवाले यातायात तथा संचार के साधन, तथा
- (iii) भूमि का उपयोग करने वाले, कृषि, उद्योग आदि कार्यों का वितरण एवं गहनता प्रतिरूप किसी भी संकेन्द्रीय प्रदेश (Nodal Region) की परिसीमा में (जिसका निर्धारण किसी केन्द्रस्थल के चतुर्दिक कार्यात्मक संगठन के आधार पर किया जाता है, परिणामस्वरूप ऐसे प्रदेश आर्थिक-तंत्र के संगठनात्मक स्वरूप के अध्ययन हेतु सार्थक आधार प्रस्तुत करते हैं) अर्थतंत्र का संगठन, आवागमन एवं परिचलन

से प्रारंभ होता है। कृषि, उद्योग, परिवहन इत्यादि विभिन्न गौण कारकों की सक्रियता के कारण समान सापेक्षिक स्थिति में नहीं मिलते। विभिन्न देशों में इनका सापेक्षिक विन्यास समान प्रतिरूप का होते हुए भी भिन्न होता है।

2. प्राविधिक/तकनीकी विकास क्रम के प्रसंग में इस कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया : अर्थतंत्र का भूवैन्यासिक संगठन (Spatial Organisation) सतत परिवर्तनशील रहता है। इसका मुख्य कारण तकनीकी ज्ञान का विकास है। यह तकनीकी विकास ऊर्जा के उपयोग एवं नियंत्रण पर निर्भर करता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि विश्व के विभिन्न भागों में ऊर्जा के उपयोग एवं नियंत्रण का स्तर अलग-अलग है और इसी के कारण उनके विकास के स्तर में विभिन्नता पाई जाती है। अतः भूवैन्यासिक प्रतिरूप समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि तत्कालीन ऊर्जा स्रोत एवं उनका नियंत्रण (उपयोग) किस प्रकार का है तथा इस पर आधारित तकनीकी विकास किस स्तर की है? प्रादेशिक अर्थतंत्र एवं गुणात्मक जीवन-स्तर, उत्पादन प्रक्रिया एवं परिवहन-संचार व्यवस्था से संबंधित तकनीकी विकास का परिणाम है और एक में परिवर्तन होने पर दूसरे के स्वरूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्रिया-कलाप एवं तकनीकी विकास की अन्तर्प्रक्रिया एवं उस पर आधारित अर्थतंत्र के स्वरूप में प्रादेशिक एवं सामयिक (काल-क्रमिक) विभिन्नता का अध्ययन करना है।
3. अन्तर्प्रादेशिक एवं प्रादेशिक अन्तर्प्रक्रिया : प्रत्येक प्रादेशिक अर्थतंत्र का भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप अथवा उसका काल-क्रमिक विकास विशिष्ट होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होता है। प्रत्येक प्रदेश के अर्थतंत्र की विशेषताएँ एवं विशिष्टताएँ अपने निकटवर्ती एवं दूर के प्रदेशों के अर्थतंत्र एवं उसके विकास-क्रम से किसी-न-किसी रूप से जुड़ी होती हैं। वस्तुतः लघुतम प्रादेशिक इकाई का अर्थतंत्र भी किसी-न-किसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व के अर्थतंत्र से जुड़ा होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण विश्व के अनेको प्रादेशिक अर्थतंत्र एक-दूसरे से अलग एवं विशिष्ट होते हुए भी एक वृहदतंत्र में जुड़े हुए हैं। अन्तर्प्रादेशिक एवं प्रादेशिक अन्तर्प्रक्रिया, प्रादेशिक विशेषीकरण एवं परिवहन तथा संचार के साधनों के स्वरूप पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण से आर्थिक भूगोल को प्रादेशिक-आर्थिक अन्तर्प्रक्रिया एवं उसके भूवैन्यासिक संगठनात्मक परिणामों का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। अन्य शब्दों में आर्थिक भूगोल पदानुक्रमिक अर्थतंत्र का अन्तर्प्रक्रियात्मक विश्लेषण भी करता है।
4. उपरोक्त तीनों का पर्यावरण (विशेषतः पारिस्थितिकी संतुलन) तथा दीर्घकालीन परिपेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन : यदि किसी भी प्रदेश विशेष के अर्थतंत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाए तो स्पष्ट होगा कि अर्थतंत्र तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है तथा परस्पर अनुक्रियात्मक (Reciprocal) प्रभाव पड़ता है। एक ओर जहाँ अर्थतंत्र की मूल विशेषताएँ पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों पर आधारित होती हैं तो दूसरी ओर तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप अर्थतंत्र में कार्यात्मक गहनता का दबाव पर्यावरण पर पड़ता है। यह दबाव जब कभी अतिशयता की सीमा पर पहुँचने लगता है तो पारिस्थितिकी संतुलन भंग होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर, पर्यावरण के संसाधनों का सम्यक् न होने पर निर्धनता परिलक्षित होती है। अतः दोनों पक्षों के मध्य एक ऐसे सम्यक् एवं अभिष्ट अंतर्संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है जिससे प्रदेश के निवासियों को गुणात्मक जीवन स्तर प्राप्त हो सके। हर प्रकार के संसाधन उपयोग हेतु समुचित तकनीकी विकास का सहारा लेना आवश्यक होता है, जिससे संसाधन एवं गुणात्मक जीवन-स्तर का सम्यक् संबंध स्थापित हो सके। यही आर्थिक भूगोल के अध्ययन का मूल उद्देश्य है। अतः अर्थतंत्र के भूवैन्यासिक संगठन का इस उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से दीर्घकालीन

परिपेक्ष्य में समायोजन करना आर्थिक भूगोल में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य को केन्द्र में रखकर रूडोल्फ वेटगेन्स ने आर्थिक भूगोल की निम्न परिभाषा दी—“आर्थिक भूगोल, विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी की संसाधनता तथा मनुष्य के आर्थिक कार्यों की अन्योन्यक्रिया का अध्ययन एवं विशेषतया संबंधित सार्थक परिणामों (गुणात्मक जीवन-स्तर) के वितरण की व्याख्या करता है।”

"Economic Geography is a study of the interaction between (a) The earth space in the fulfilment and (b) economic man, with particular attention to explanations of the distribution of the pertinent consequences of such interaction."